

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1856
दिनांक 31 जुलाई 2025

कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन

†1856 डॉ. शशि थरूर:

क्या *पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान हुए कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;
- (ख) क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में लगभग 2.9 प्रतिशत की गिरावट आई है और आयातित कच्चे तेल में भी 6.4 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार कच्चे तेल के आयात के लिए अस्थिर वैश्विक बाजारों पर निर्भरता कम करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन निम्नानुसार है:-

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
कच्चा तेल (एमएमटी में)	30.5	29.7	29.2	29.4	28.7

स्रोत – पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी), हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच)

(ख) पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में कच्चे तेल के उत्पादन में 2.23% की कमी हुई है तथा कच्चे तेल के आयात में 3.8% की वृद्धि देखने में आई है।

(ग) और (घ) कच्चे तेल की आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी क्षेत्र-विशेष से कच्चे तेल पर निर्भरता सम्बन्धी जोखिम कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम (पीएसयूज) ने कच्चे तेल की बास्केट को विविधीकृत किया है एवं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अवस्थित देशों यथा,- मध्य-पूर्व, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आदि से कच्चा तेल अधिप्राप्त कर रहे हैं।

सरकार द्वारा कच्चे तेल के आयात में कमी लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए पूरे देश में

ईंधन/फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर माँग प्रतिस्थापन करना, एथेनॉल, दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल, संपीड़ित जैव गैस और जैव डीजल जैसे नवीकरणीय और वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा, रिफाइनरी प्रक्रिया सुधार, ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण को बढ़ावा देना, आदि शामिल हैं। सरकार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है। 2025 के जून माह के दौरान मिश्रण का प्रतिशत लगभग 19.92% पहुँच गया। इसके परिणाम स्वरूप ईएसवाई 2013-14 से ईएसवाई 2023-24 तक लगभग 1.09 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। ऑटोमोटिव ईंधन के रूप संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल भी शुरू की गई है।

इसके अलावा, सरकार कच्चे तेल पर आयात निर्भरता कम करने के निमित्त निम्नलिखित कदम उठा रही है –

- क. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मौद्रिकरण के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के अन्तर्गत रियायतों, अवधि बढ़ाए जाने और स्पष्टीकरणों के लिए नीति, 2014
- ख. खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, 2015
- ग. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016
- घ. उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की अवधि बढ़ाए जाने के लिए नीति, 2016 और 2017
- ङ. कोल बेड मिथेन के शीघ्र मौद्रिकरण के लिए नीति, 2017
- च. राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी की स्थापना, 2017
- छ. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के अन्तर्गत तलछटीय बेसिनों में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन, 2017
- ज. उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के विस्तार के लिए नीतिगत ढांचा, 2016 और 2017
- झ. तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी प्रणाली को बढ़ावा/प्रोत्साहन देने की नीति, 2018
- ञ. मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज), कोल बेड मिथेन (सीबीएम) संविदाओं तथा नामांकन क्षेत्रों के अन्तर्गत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत ढांचा, 2018
- ट. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020
- ठ. बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए कम रॉयल्टी दरों, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और श्रेणी II और III बेसिनों के अन्तर्गत ओएएलपी ब्लॉक में चरण- I में कोई वेधन प्रतिबद्धता नहीं है।
- ड. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर 'निषिद्ध' क्षेत्र मुक्त करना जो दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध था।
